अमरीका और ईरान परमाणु सौदा: अस्थायी अंतराल

*डा.स्तुति बनर्जी**

विगत एक वर्ष के दौरान अमरीका और ईरान परमाणु सौदे को अंतिम रूप देने का प्रयास करते रहे हैं; एक ऐसा करार, जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को इतना सीमित कर सके कि यदि ईरान इस करार/समझौते की अनदेखी करने का निर्णय लेता भी है तो भी परमाणु बम हेतु पर्याप्त सामग्री बनाने में इसे कम से कम एक वर्ष का समय लगे। इससे अमरीका तथा अन्य वार्ताकार राष्ट्रों को होनेवाली गतिविधियों पर कूटनीतिक तरीके से कार्रवाई करने और/अथवा प्रतिबंध लगाने का अवसर मिल जाएगा, जो यह सुनिश्चित करेगा कि सैन्य विकल्प अंतिम उपाय हो।

ये वार्ताएं उन उपायों पर केंद्रित रही हैं जो तुरंत परमाणु बम बना लेने की ईरान की क्षमता को सीमित करेंगे, लेकिन परमाणु शक्ति और अनुसंधान के जिस शांतिपूर्ण कार्यक्रम पर ईरान जोर देता है, उसे जारी रखने हेतु क्षमता बनाए रखने की अनुमति भी इसे देंगे। ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से (दूर) रखना अमरीकी सुरक्षा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और इस विचार से ही हाल की वार्ताओं, जो किसी करार तक नहीं पहुंच सकीं, के लिए विस्तारित समय सीमा प्रदान की गई है। जहां एक ओर कुछ नीति-निर्माता इसे एक स्वागतयोग्य संकेत के रूप में देखते हैं (जो इस बात का) साक्ष्य है कि दोनों देश गतिरोध का हल तलाशने के लिए प्रतिबद्ध हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ अन्य नीति-निर्माता इसे गहरे अविश्वास के एक और प्रतीक के रूप में देखते हैं जो संबंधों में रूकावट पैदा कर रहा है। ईरान को समय-सीमा में रियायत दिए जाने पर विरोधियों द्वारा अमरीकी प्रशासन की आलोचना की गई है, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि इस रियायत का उपयोग ईरान द्वारा अपनी (परमाणु) क्षमता तथा प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए किया जाएगा। उन्होंने अधिक कड़े प्रतिबंधों की मांग की है, एक ऐसी मांग जिसे वर्तमान में अमरीकी प्रशासन द्वारा दरकिनार कर दिया गया है।

ईरान ने बार-बार दावा किया है कि वह परमाणु हथियारों का निर्माण नहीं कर रहा है और वह महसूस करता है कि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस देश (ईरान) के विरूद्ध पक्षपात से ग्रसित होकर अन्यायपूर्ण व्यवहार किया गया है। ईरान परमाणु प्रौद्योगिकी का उपयोग हथियारों के लिए नहीं करने की अपनी प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में एक धार्मिक अध्यादेश, *फतवा* का हवाला देता है जो परमाणु हथियारों के विकास के विरूद्ध उनके सर्वोच्च नेता द्वारा जारी किया गया है। तथापि, इस आश्वासन को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संदेह की नज़र से देखता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस कार्यक्रम की गोपनीयता और परमाणु अप्रसार संधि (एनटीपी) से ईरान के हट जाने को उसके संदिग्ध व्यवहार के प्रमाण के रूप में पेश करता है, जो आर्थिक प्रतिबंधों जैसी कार्रवाइयों का कारण बना।

ईरान के लोग भी अमरीकी कार्रवाइयों के प्रति समान रूप से सशंकित हैं। वे सद्दाम हुसैन के हश्र का हवाला देते हैं, जिन्होंने सभी अंतर्राष्ट्रीय संकल्पों का अनुपालन किया और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी निरीक्षकों को निरीक्षण की अनुमति दी, फिर भी, उन्हें अमरीका द्वारा सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। दोनों देशों के बीच के इतिहास को देखते हुए, ईरान को आशंका है कि यदि इसने अपने परमाणु हितों की रक्षा करने के लिए वार्ता नहीं की तो इसका भी वही हश्र होगा। ईरान के लिए, उसका परमाणु कार्यक्रम गर्व का विषय है और एक क्षेत्रीय शक्ति बनने की अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने की दिशा में उठाया गया कदम है। ऐसी स्थिति में, वह चाहता है कि अमरीका उससे बराबर के भागीदार की तरह व्यवहार करे और बराबर के भागीदार से कम की तरह किए गए किसी भी व्यवहार पर अपनी नाराज़गी जाहिर करता है।

अपने परमाणु कार्यक्रम का परित्याग करने के लिए ईरान पर दबाव डालने के प्रयास में उसपर थोपे गए क्रमश:/क्रमिक प्रतिबंधों के वांछित प्रभाव नहीं पड़े। घरेलू स्तर पर, गैलप द्वारा कराया गया एक सर्वेक्षण (फरवरी, 2013) दर्शाता है कि ईरान की 63 प्रतिशत जनता प्रतिबंधों के कारण होने वाली कठिनाइयों के बावजूद (परमाणु) कार्यक्रम का समर्थन करती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, प्रतिबंधों के बावजूद, ईरान को एशिया के कुछ देशों जैसे चीन, ताइवान और भारत को तेल बेचने की अनुमति दी गई है। चीन ने अधिक मात्रा में तेल का आयात करना प्रारंभ कर दिया है जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था को बहुप्रतीक्षित कुछ राहत मिल रही है। चीनी सीमा शुल्क आंकड़ों के अनुसार, चीन ने वर्ष 2014 के पहले छह महीनों में 630000 बैरल तेल का आयात किया जो वर्ष 2013 में इसी अवधि के दौरान किए गए आयात से 48 प्रतिशत अधिक है। इन सीमित रियायतों को मंजूरी दिए जाने से पहले चीन अपेक्षाकृत बड़ी मात्रा में ईरान से कच्चे तेल खरीद रहा था। यह तथ्य जापान और श्रीलंका जैसे कुछ अन्य देशों के लिए भी सच है।

ईरान हाल ही में रूस के साथ 20 अरब अमरीकी डॉलर के 'सामान-के-बदले-तेल' सौदे की रूपरेखा पर हस्ताक्षर करने में सफल हो गया है। 'पश्चिम' के साथ रूस के बदलते संबंधों और रूस, जो अमरीका और यूरोपीय संघ को चुनौती देने की अपनी इच्छा का प्रदर्शन कर रहा है, के उत्थान को देखते हुए यह एक महत्वपूर्ण घटना है जिसका अर्थ यह है कि ईरान अपनी अर्थव्यवस्था को कायम रखने के लिए रूस के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल कर सकता है और बहुप्रतीक्षित अन्तर्राष्ट्रीय समर्थन भी जुटा सकता है। इस प्रकार, अमरीका द्वारा ईरान को अकेला पड़ जाते हुए देखने (की इच्छा) को विदेश नीति के औजार की तरह इस्तेमाल किया जाना इतना प्रभावशाली नहीं होगा।

स्वयं अमरीका ईरान के साथ अपने संबंध सुधारने का प्रयास कर रहा है। (ऐसी स्थिति में) जब मध्य पूर्व (क्षेत्र) सीरिया और इराक में अशांति का सामना कर रहा है, अमरीका सऊदी अरब और इजराइल जैसे अपने सहयोगियों के सरोकारों/चिन्ताओं से संतुलन बनाते हुए इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने में ईरान के लिए किसी भूमिका की तलाश में है। अमेरिका के लिए परमाणु सौदा केवल परमाणु मुद्दों के संकुचित दायरे तक ही सीमित नहीं रह गया है। अमेरिका के लिए इस क्षेत्र में और अपने घर/देश में भी इसके राजनीतिक परिणाम होंगे।

यह करार ऐसा होना चाहिए जो न केवल वार्ताकार (देशों) को स्वीकार्य हो बल्कि इसके पश्चात इसका अनुसमर्थन संबंधित देशों की संसद द्वारा भी किया जाए। ईरान के विदेश मंत्री, जावद जारिफ सरकार के भीतर ही परस्पर विरोधी विचारों का सामना कर रहे हैं। तथापि, सर्वोच्च नेता तथा उस राष्ट्र के सभी मामलों पर अंतिम निर्णयकर्ता अयातुल्ला अली खमैनी ने सार्वजनिक तौर पर किसी 'निष्पक्ष' सौदे के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है और इस बात पर बहुत कम संदेह है कि ऐसा सौदा ईरान की संसद द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा। अमरीकी विदेश मंत्री, श्री जॉन केरी के सामने भी कड़ी चुनौती है। वर्तमान में अमरीकी कांग्रेस में रिपब्लिकन (पार्टी) का बहुमत है, जो एक ऐसी पार्टी है जिसने ईरान के विरूद्ध कड़े प्रतिबंधों की मांग की है, जबकि इस विचार का डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति तथा व्हाइट हाउस द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध किया गया है। राष्ट्रपति ओबामा और कांग्रेस के बीच अन्य मुद्दों पर मतभेदों के साथ-साथ इन मतभेदों से ईरान बेखबर नहीं है।

अमरीका स्पष्ट रूप से चाहता है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम रोका जाए। ईरान नि:संदेह चाहता है कि वह यथासंभव अपनी क्षमता बनाए रखे और सभी प्रतिबंध हटा लिए जाएं। दोनों देशों को अब एक ऐसे करार पर वार्ता करनी है जो उन्हें अपने-अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने दे और यह अमरीका तथा ईरान के बीच एक नए रिश्ते के निर्माण की प्रक्रिया का पहला कदम हो सकता है।

*_डॉ. स्तुति बनर्जी विश्व मामलों की भारतीय परिषद, नई दिल्ली में अनुसंधान अध्येता हैं।_